

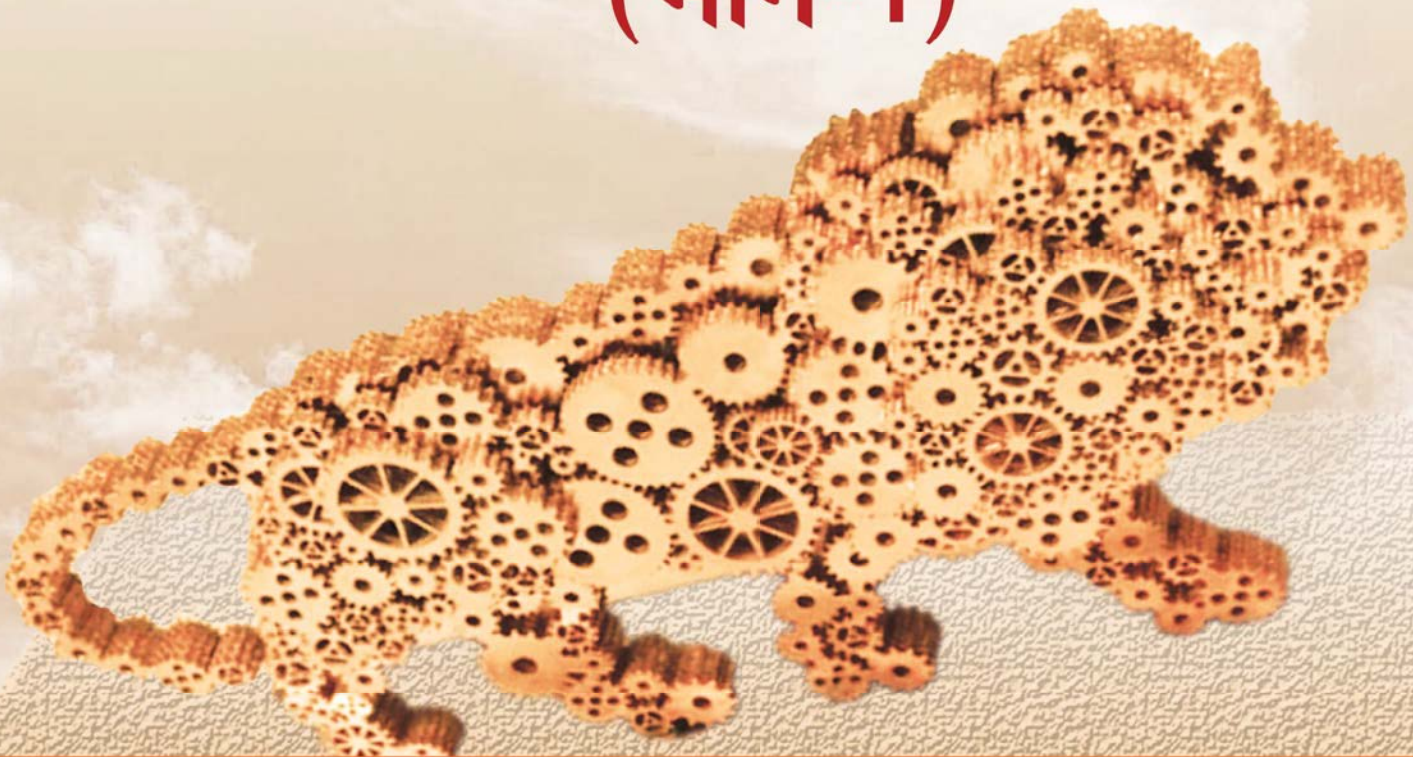
Think
IAS... 



Think
Drishti

राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

भारत एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था (भाग-1)



दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम (Distance Learning Programme)

Code: RJPM09



राजस्थान लोक सेवा आयोग (RAS/RTS)

भारत एवं राजस्थान की अर्थव्यवस्था (भाग-1)



641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

दूरभाष : 011-47532596, 8750187501

टोल फ्री : 1800-121-6260

Web : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें

 www.facebook.com/drishtithevisionfoundation

 www.twitter.com/drishtiiias

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय	5-21
1.1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था	5
1.2 भारतीय अर्थव्यवस्था : प्रकृति एवं वर्तमान प्रवृत्तियाँ	8
1.3 अर्थव्यवस्था के क्षेत्र	10
1.4 आर्थिक विकास एवं आर्थिक संवृद्धि	10
1.5 आर्थिक विकास के मापन	14
1.6 आर्थिक विकास की रणनीति	17
2. राष्ट्रीय आय	22-38
2.1 राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा	22
2.2 राष्ट्रीय आय को मापने की विधियाँ	29
2.3 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय	35
3. भारत में आर्थिक नियोजन	39-51
3.1 नियोजन : अभिप्राय, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषताएँ एवं प्रकार	39
3.2 योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग	40
4. समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन	52-80
4.1 समावेशी विकास	52
4.2 समावेशी संवृद्धि	53
4.3 वित्तीय समावेशन	53
4.4 सामाजिक समावेशन	57
4.5 गरीबी	59
4.6 बेरोज़गारी	69
5. कृषि	81-122
5.1 आर्थिक विकास में कृषि का योगदान	81
5.2 भारतीय कृषि की विशेषताएँ	82
5.3 भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार	87
5.4 हरित क्रांति	90
5.5 सिंचाई	94
5.6 कृषि साख	95
5.7 कृषि क्षेत्र से संबंधित प्रौद्योगिकी	101
5.8 खाद्य सुरक्षा एवं बफर स्टॉक	104

5.9	सार्वजनिक वितरण प्रणाली : उद्देश्य एवं सीमाएँ	109
5.10	सब्सिडी : खाद्य सब्सिडी, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सब्सिडी	110
5.11	कृषि से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रक	112
5.12	कृषि से संबंधित योजनाएँ	115
6.	उद्योग एवं सेवा क्षेत्र	123–178
6.1	औद्योगीकरण : आशय एवं उत्पादन के क्षेत्र	123
6.2	भारतीय औद्योगिक नीति	124
6.3	उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण	129
6.4	निवेश एवं विनिवेश	138
6.5	सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग	140
6.6	भारत में सार्वजनिक उद्यम : महारत्न, नवरत्न एवं मिनीरत्न	141
6.7	भारत में उद्योग	143
6.8	औद्योगिक अस्वस्थता/रुग्णता	150
6.9	औद्योगिक वित्त	152
6.10	औद्योगीकरण से संबंधित प्रमुख योजनाएँ	156
6.11	सेवा क्षेत्र में भारतीय परिदृश्य	162
6.12	सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख नीतियाँ एवं योजनाएँ	169
6.13	आधारभूत अधोसंरचना	174
7.	राजस्थान अर्थव्यवस्था : वृहद् परिदृश्य	179–200
8.	राजस्थान : आर्थिक नियोजन	201–211
9.	राजस्थान में विकास के विविध आयाम	212–228
9.1	सामाजिक विकास के आयाम	212
9.2	क्षेत्रीय विकास के आयाम	218
9.3	मानव विकास के आयाम	220
9.4	बीमारू की अवधारणा	225
10.	बैंकिंग तथा वित्तीय प्रणाली	229–272
10.1	मुद्रा और बैंकिंग	229
10.2	परिसंपत्तियाँ एवं देयता सृजन	247
10.3	भारतीय रिज़र्व बैंक	248
10.4	शेयर बाज़ार, प्रतिभूति बाज़ार एवं सेबी	253
10.5	भारत में म्यूचुअल फंड एवं बीमा क्षेत्र	257
10.6	डिपॉजिटरी प्रणाली, कमोडिटी एक्सचेंज एवं डेरिवेटिव्स	259
10.7	मुद्रास्फीति एवं अवस्फीति	260

भारतीय अर्थव्यवस्था : सामान्य परिचय (Indian Economy : General Introduction)

प्राचीन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था समृद्ध एवं विकसित थी। मध्यकाल में भारत का व्यापार अरब देशों, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों तथा यूरोपीय देशों तक फैला हुआ था, लेकिन 18वीं सदी में भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, फलतः वह दयनीय स्थिति में आ गई, लेकिन स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में गति प्रदान करने तथा विकास की निरंतरता को बनाए रखने हेतु योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया गया। इसी क्रम में वर्ष 1991 में नई आर्थिक प्रणाली लागू कर उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा दिया गया ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर बढ़ाई जा सके।

1.1 अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था (*Economics and Economy*)

अर्थशास्त्र (*Economics*)

अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें हम उत्पादन, उपभोग, विनिमय एवं वितरण के बारे में अध्ययन करते हैं। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र की अवधारणा में बैंकिंग, राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आदि को भी शामिल किया जाता है।

अर्थशास्त्र की शाखाएँ (*Branches of economics*)

अर्थशास्त्र की दो शाखाएँ हैं, जो निम्नलिखित हैं-

1. व्यष्टि अर्थशास्त्र (*Micro economics*)

- व्यष्टि-अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे- एक व्यक्तिगत फर्म या उत्पादन गृह अथवा एक व्यक्तिगत उपभोक्ता।
- इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा उस उत्पाद की कीमत का निर्धारण किया जाता है।

2. समष्टि अर्थशास्त्र (*Macro economics*)

- समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक गतिविधियों एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है।
- इसके अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर को निर्धारित किया जाता है।
- रोजगार, मुद्रा, सामान्य कीमत, राष्ट्रीय आय, आर्थिक विकास आदि का अध्ययन समष्टि अर्थव्यवस्था से संबंधित है।

अर्थव्यवस्था (*Economy*)

किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए मुद्रा (Money) को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही **अर्थव्यवस्था** कहलाती है। 'अर्थव्यवस्था' शब्द को किसी देश के साथ जोड़कर प्रायः पूर्ण बनाया जाता है, जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था आदि। अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली अवधारणा है जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं उनके स्तर से होता है। वह क्षेत्र एक गाँव, राज्य या संपूर्ण देश भी हो सकता है।

आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय को शामिल किया जाता है-

उत्पादन (Production) : उत्पादन का अर्थ आगतों या कारकों को उत्पाद में बदलना है।

उपभोग (Consumption) : अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही 'उपभोग' कहलाता है।

संतुलित विकास (Balance development)

यह विकास 'बहुमुखी विकास के सिद्धांत' पर आधारित है। इसमें अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों- कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का एक साथ विकास किया जाता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों के तैयार उत्पादों के लिये बाजार मिल सके और अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों में संतुलन की स्थिति प्राप्त की जा सके। इस प्रकार के विचार रखने वाले अर्थशास्त्रियों में रेगनर नर्कसे, लिबिस, ऐलिन यंग, रोजेनस्टीन रोडॉ आदि प्रमुख हैं।

ध्यातव्य है कि संतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्री रोजेनस्टीन रोडॉ विकास की मंद प्रक्रिया से असहमत थे। उनके अनुसार, नियोजन का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को उसके निम्न-स्तरीय स्थिति से तीव्रता के साथ बाहर निकालकर संचयी विकास पर आरूढ़ करने का होना चाहिये, जिससे आर्थिक ढाँचे की जड़ता भंग हो जाए और अर्थव्यवस्था उच्च उत्पादकता और वास्तविक आय की ओर अग्रसर हो सके।

असंतुलित विकास (Imbalance development)

असंतुलित विकास में पूर्व में चयनित विकास के संभावनाशील क्षेत्रों में ही विकास किया जाता है, जिनके लिये पर्याप्त सुविधाएँ मौजूद हैं। अतः शुरुआत में विकास उन्हीं चयनित क्षेत्रों में किया जाना चाहिये जो विकास को अधिक तीव्र गति प्रदान करें। इसके लिये पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों को वरीयता दी जा सकती है। ऐसा करने से उपभोक्ता केंद्रित उद्योगों के विकास के लिये आधार तैयार हो जाता है। बाद में उपभोक्ता केंद्रित उद्योगों का विकास किया जा सकता है। यह रणनीति उन अल्पविकसित एवं विकासशील देशों के लिये बहुत उचित है, जिनके साधन बहुत सीमित हैं। वे अपने विकास को धीरे-धीरे क्रमानुसार गति प्रदान कर सकते हैं।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- यदि किसी अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में द्वितीय क्षेत्र अर्थात् औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा 50% हो तथा इसी अनुपात में इस क्षेत्र पर लोगों की आजीविका के लिये निर्भरता हो तो उस अर्थव्यवस्था को 'औद्योगिक अर्थव्यवस्था' कहा जाता है।
- मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता होती है।
- व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेड मार्क कहा जाता है।
- निर्माण एवं विनिर्माण द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र वानिकी, मत्स्यन तथा खनन एवं उत्खनन प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं।
- श्रम, भूमि, पूंजी तथा उद्यमशीलता उत्पादन के कारक हैं।
- सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर भारत विश्व की सातवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- वर्ष 1776 में एडम स्मिथ द्वारा प्रकाशित पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशंस' थी।
- बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, शिक्षा तथा पर्यटन आदि तृतीयक क्षेत्र से संबंधित हैं।
- भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण यहाँ श्रम आधिक्य की स्थिति रहती है।
- आय वितरण में असमानता, जीवन निर्वाह का निम्न स्तर, व्यापक बेरोजगारी, असंतुलित आर्थिक विकास तथा औद्योगीकरण का निम्न स्तर इत्यादि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ हैं।
- सामाजिक प्रगति सूचकांक तीन व्यापक आयामों मानव की बुनियादी आवश्यकताएँ, सुख के आधार और अवसर पर आधारित है।
- मानव विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा जारी की जाती है।

- पूंजी निर्माण के तीन आवश्यक घटकों में बचत, बचत के गतिशीलन हेतु वित्तीय संस्थाएँ तथा विनियोग को शामिल किया जाता है।
- भारत में पूंजी निर्माण के आँकड़े एकत्रित करने का काम भारतीय रिज़र्व बैंक एवं केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है।
- किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति वास्तविक आय है।
- लैगाटम समृद्धि सूचकांक यह दर्शाता है कि किस प्रकार समृद्धि प्राप्त की जा सकती है और किस प्रकार समृद्धि विश्व में बदलाव ला रही है।
- श्रम की न्यून कार्यक्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यून दर तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख लक्षण हैं।
- भारत को निकट भविष्य में 8% आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने के लिये श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास करना चाहिये।
- कारोबार सुगमता सूचकांक विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मानव विकास प्रतिवेदन, 2015 के अनुसरण में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-
RAS (Pre) 2016
 1. भारत का स्थान 188 देशों में 130वाँ है।
 2. मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रतिव्यक्ति आय पर आधारित है।
 3. ब्रिक्स के अन्य देशों के मुकाबले भारत निम्नतम स्थान पर है।

उपरोक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

 - (1) केवल 1 और 2
 - (2) केवल 2 और 3
 - (3) केवल 2
 - (4) 1, 2 और 3
2. मानव विकास रिपोर्ट, 2013 के अनुसार, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्रम है- **RAS (Pre) 2013**
 - (1) 133
 - (2) 134
 - (3) 136
 - (4) 139
3. निम्नलिखित में से कौन-सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है? **RAS (Pre) 2013**
 - (1) वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
 - (2) वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि।
 - (3) किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
 - (4) जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि।
4. मानव विकास सूचकांक एक संयुक्त सूचकांक है- **RAS (Pre) 2013**
 - (1) पोषण संबंधी स्थिति, जीवन की गुणवत्ता एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
 - (2) निर्धनता, जीवन प्रत्याशा एवं शैक्षिक उपलब्धि
 - (3) जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि एवं प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
 - (4) मुद्रा स्फीति, बेरोजगारी और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद
5. भारत में निकट भविष्य में 8% या अधिक आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करने में सर्वाधिक सहयोग किस तत्त्व से मिल सकता है? **RAS (Pre) 2013**
 - (1) देश में श्रम शक्ति का तीव्र गति से कौशल विकास किया जाए।
 - (2) सभी अवरुद्ध या रुके हुए उत्पादक प्रोजेक्टों का क्रियान्वयन किया जाए।
 - (3) व्यवसाय-व्यापार करने को आसान बनाने में तेज़ रफ्तार से वृद्धि की जाए।
 - (4) वस्तु व सेवा कर को बिना विलंब के 1 अप्रैल, 2016 से लागू किया जाए।

6. निम्नलिखित में से कौन-सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है?
- प्राथमिक क्षेत्र
 - द्वितीयक क्षेत्र
 - तृतीयक क्षेत्र
 - सभी तीनों बराबर योगदान देते हैं।
7. निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का कारक नहीं है?
- श्रम
 - भूमि
 - पूंजी
 - उपभोग
8. निम्नलिखित में से कौन-कौन से कारक आर्थिक संवृद्धि एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं?
- प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता
 - पूंजी निर्माण की दर
 - तकनीकी विकास
 - मानव संसाधन
- कूट:
- केवल 1, 2 और 3
 - केवल 2, 3 और 4
 - केवल 1, 2 और 4
 - 1, 2, 3 और 4
9. संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है?
- महबूब-उल-हक
 - जगदीश भगवती
 - जोसेफ स्टिग्लिज
 - अमर्त्य सेन
10. भारत में पूंजी निर्माण आँकड़े एकत्रित करने का काम कौन करता है?
- भारतीय रिज़र्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
 - भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक
 - भारतीय रिज़र्व बैंक और सभी वाणिज्यिक बैंक
 - केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण
11. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा कथन सत्य है?
- आर्थिक संवृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है। यह राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि को प्रदर्शित करती है।
 - आर्थिक विकास एक स्वचालित प्रक्रिया है।
 - आर्थिक विकास अर्थव्यवस्था में केवल मात्रात्मक परिवर्तन लाता है।
 - आर्थिक संवृद्धि की अवधारणा आर्थिक विकास की तुलना में अत्यधिक व्यापक है।
12. 'कारोबार सुगमता सूचकांक' निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है?
- विश्व बैंक
 - अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
 - विश्व व्यापार संगठन
 - इनमें से कोई नहीं
13. विकास के मानवीय पक्ष पर निम्नलिखित में से किस एक ने सबसे पहले बयान केंद्रित किया?
- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
 - समन्वित ग्रामीण विकास योजना
 - विश्व विकास प्रतिवेदन
 - सामुदायिक विकास योजना
14. अर्थव्यवस्था में जब प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों का एक साथ विकास होता है तो यह विकास कहलाता है—
- संतुलित विकास
 - असंतुलित विकास
 - स्थायी विकास
 - उपरोक्त में से कोई नहीं
15. 'मानव विकास रिपोर्ट' पहली बार किस वर्ष जारी की गई?
- 1991
 - 1990
 - 1992
 - 1995
16. भारतीय अर्थव्यवस्था को किस श्रेणी में रखा जा सकता है?
- एक विकसित अर्थव्यवस्था
 - एक विकासशील अर्थव्यवस्था
 - एक गतिहीन अर्थव्यवस्था
 - एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था
17. 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' वह अर्थव्यवस्था है जिसमें—
- सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व हो।
 - आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग हो।
 - वृद्ध एवं कुटीर उद्योगों का सह-अस्तित्व हो।
 - उपर्युक्त में से कोई नहीं।

उत्तरमाला

1. (4) 2. (3) 3. (2) 4. (3) 5. (1) 6. (3) 7. (4) 8. (4) 9. (1) 10. (1)
 11. (1) 12. (1) 13. (1) 14. (1) 15. (1) 16. (2) 17. (1)

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 15-20 शब्दों में दीजिये)

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. मानव विकास सूचकांकों के निरूपण में प्रयुक्त आधारभूत संकेतक बताइये। | 4. जीवन के भौतिक गुणवत्ता सूचकांक के घटक। |
| 2. बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताइये। | 5. पूंजी निर्माण |
| 3. आर्थिक संवृद्धि दर से आप क्या समझते हैं? | 6. द्वितीयक क्षेत्र |
- RAS (Mains) 2013**

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 50-50 शब्दों में दीजिये)

- | | |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1. विकसित अर्थव्यवस्था क्या है? इसके लक्षण बताइये। | 4. भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियों का उल्लेख करें। |
| 2. अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिये। | 5. पूंजी उत्पाद अनुपात से क्या तात्पर्य है? टिप्पणी करें। |
| 3. आर्थिक विकास से आप क्या समझते हैं? | |

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100 या 200 शब्दों में दीजिये)

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का उल्लेख करें। | 3. आर्थिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का परीक्षण कीजिये। |
| 2. आर्थिक संवृद्धि तथा आर्थिक विकास में क्या अंतर है? विवेचना कीजिये। | |

राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो नीति-निर्माण एवं कल्याणकारी राज्य की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय आय देश की उत्पादन क्रियाओं की माप होती है। राष्ट्रीय आय की गणना के अंतर्गत प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण के द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने व प्राथमिकताओं को स्थापित करने में सहायता मिलती है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के आर्थिक निष्पादन की जानकारी का प्रमुख साधन राष्ट्रीय आय है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिये वर्ष 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष पी.सी. महालनोबिस थे।

2.1 राष्ट्रीय आय का अर्थ एवं अवधारणा (Meaning and Concept of National Income)

राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी राष्ट्र की एक वर्ष के दौरान आर्थिक क्रियाओं के परिणामस्वरूप उत्पादित अंतिम 'वस्तुओं एवं सेवाओं' के मौद्रिक मूल्य से होता है। दूसरे शब्दों में, किसी एक लेखा वर्ष की अवधि के अंतर्गत किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना में देश के निवासियों द्वारा घरेलू सीमा एवं विदेशों से प्राप्त अर्जित आय को सम्मिलित किया जाता है।

राष्ट्रीय आय की अवधारणा (Concept of national income)

- राष्ट्रीय आय में किसी एक समय पर उपलब्ध वस्तुओं के स्टॉक को नहीं, बल्कि किसी समयावधि में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है।
- राष्ट्रीय आय की अवधारणाओं में सभी वस्तुओं एवं सेवाओं की बाजार कीमत पर गणना की जाती है और एक वस्तु की कीमत एक बार ही शामिल की जाती है, इसलिये अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही शामिल किया जाता है, ताकि दोहराव से बचा जा सके।

राष्ट्रीय आय से संबंधित विभिन्न अवधारणाएँ निम्नलिखित हैं-

सकल घरेलू उत्पाद (Gross domestic product-GDP)

किसी देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत नागरिकों एवं गैर-नागरिकों द्वारा एक वित्तीय वर्ष (भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च) में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं।

विदेशियों द्वारा पूंजी एवं तकनीकी का जो निवेश भारत के घरेलू क्षेत्र में किया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्य को भी सकल घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाता है।

सकल घरेलू उत्पाद को निम्नलिखित सूत्र के माध्यम से व्यक्त किया जाता है-

$$\text{सकल घरेलू उत्पाद (GDP)} = \text{उपभोग (C)} + \text{निवेश (I)} + \text{सरकारी व्यय (G)} + [\text{कुल आयात (X)} - \text{कुल निर्यात (M)}]$$

सकल राष्ट्रीय उत्पाद (Gross national product-GNP)

किसी देश के नागरिकों द्वारा घरेलू सीमा के अंदर अथवा बाहर एक निश्चित समयावधि, सामान्यतः एक वर्ष, में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं।

आर्थिक नियोजन (आयोजन) योजनाबद्ध तरीके से किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिये आवश्यक है। आर्थिक नियोजन में सामाजिक नियोजन की अवधारणा स्वतः ही सम्मिलित रहती है। भारत में सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के साधन के रूप में नियोजन की अवधारणा को स्वीकार किया गया है। आर्थिक नियोजन कल्याणकारी राज्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने एवं उन्नति के लिये स्वीकार किया गया है।

भारत में आर्थिक विकास की गति को तीव्रतर बनाना नीतिगत कार्यों का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ विकास के लिये अनुकूल परिवेश तैयार करना तथा लक्षित कार्यों को नियोजित तरीके से पूर्ण करने के लिये नियोजन अनिवार्य है।

3.1 नियोजन : अभिप्राय, उद्देश्य, आवश्यकता, विशेषताएँ एवं प्रकार (Planning : Significance, Objective, Requirement, Features and Type)

नियोजन का अभिप्राय (Significance of planning)

राज्य के नेतृत्व में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंधन जिससे राष्ट्रहित की प्राप्ति हेतु उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग तथा दीर्घकालिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके, साथ ही सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये प्राकृतिक, आर्थिक एवं मानवीय संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से नियंत्रण तथा समन्वय किया जा सके, अवधारणा **नियोजन** कहलाता है।

नियोजन के उद्देश्य (Objectives of planning)

- संसाधनों का सही वितरण सुनिश्चित करना।
- निर्धनता को समाप्त करना।
- बेरोजगारी दूर करना।
- आधारभूत संरचना का विकास करना।
- कृषि एवं उद्योग का विकास सुनिश्चित करना।
- सामाजिक न्याय के साथ ही साथ विकास की गति को तीव्र करना।

नियोजन की आवश्यकता (Requirement of planning)

- गरीबी, बेरोजगारी कम करने के लिये।
- निम्न उपभोग स्तर को बढ़ाने के लिये।
- गरिमाहीन जीवन शैली के उन्नयन हेतु।
- उद्योग एवं व्यापार के अभाव को कम करने के लिये।
- कौशल एवं वित्तीय संसाधनों के अभाव को कम करने के लिये।

नियोजन की विशेषताएँ (Features of planning)

- भारतीय आर्थिक नियोजन का स्वभाव निदेशात्मक है।
- आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करने में प्रोत्साहन को वरीयता दी जाती है।
- आर्थिक नियोजन का स्वरूप विकेंद्रीकृत है (सामान्यतः राष्ट्रीय महत्त्व के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को छोड़कर)।

समावेशी विकास तथा सामाजिक समावेशन (Inclusive Development and Social Inclusion)

प्रत्येक व्यक्ति समाज में समतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करता है। भारतीय समाज में कई ऐसे वर्ग हैं, जो समाज की मुख्यधारा से बहिष्कृत हैं, जैसे- दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, विकलांग, घुमंतू जातियाँ, महिलाएँ, गरीब, किन्नर एवं शरणार्थी। इन समूहों को समाज की मुख्यधारा में लाना ही सामाजिक समावेशन कहलाता है जिससे समाज का प्रत्येक व्यक्ति विकास की पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।

समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन एक-दूसरे से घनिष्ठता के साथ जुड़े हैं। जहाँ समावेशी विकास अंतिम व्यक्ति तक विकास के वितरण को सुनिश्चित करने से संबंधित है, वहीं सामाजिक समावेशन समाज के अंतिम व्यक्ति को भी वही महत्त्व दिये जाने की वकालत करता है, जो प्रथम व्यक्ति को प्राप्त है। समावेशी विकास में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सभी पहलुओं को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक समावेशन समावेशी विकास का प्रमुख आधार है। समाज में सामाजिक अपवर्चन से मुक्ति समावेशी विकास एवं सामाजिक समावेशन के द्वारा ही संभव है।

4.1 समावेशी विकास (Inclusive Development)

समावेशी विकास का आशय आर्थिक विकास की एक ऐसी अवधारणा से है, जिसमें विकास का लाभ समाज के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त हो, कोई भी वर्ग विकास से वंचित न रह जाए अर्थात् समान अवसरों के साथ-साथ विकास करना ही समावेशी विकास है।

भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना में समावेशी विकास का व्यापक रूप से उपयोग किया। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रीय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करने हेतु प्रभावी तथा संपोषणीय नीतियाँ एवं कार्यक्रम बनाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसीलिये बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) की अवधारणा का केंद्र बिंदु तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास रखा गया।

योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा व्यक्तियों द्वारा जीवन यापन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना होता है। गरीब एवं हाशिये पर रह रहे लोगों के विकास पर बल, बेहतर रहन-सहन का वातावरण, अवसरों का अधिकतम समान वितरण करने की आवश्यकता है। महिलाओं को केंद्र में रखकर उनके सशक्तीकरण पर बल देते हुए उनकी शिक्षा एवं रोजगार की ओर ध्यान देना आवश्यक है।

जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमांत कृषक, अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, घुमंतू जातियाँ और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग सामाजिक और वित्तीय समस्याओं तथा अपवर्जन से जूझ रहे हैं। ऐसे वर्ग के लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिये सरकार अपनी नीतियों में विशेष उपबंध की व्यवस्था करती है। समावेशी विकास में आर्थिक विकास की ऊँची वृद्धि दर से प्राप्त लाभ के समान वितरण को शामिल किया जाता है।

समावेशी विकास स्थापित करने के महत्वपूर्ण घटक

(Important components to establish inclusive development)

- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले सभी सामान्य एवं कमजोर वर्ग के बेरोजगारों के लिये विशेष उपबंध करना। रोजगार में वृद्धि को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ना।
- आधारभूत आवश्यक वस्तुओं तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना।
- कृषि तथा ग्रामीण विकास को सुनिश्चित करना, ताकि इस क्षेत्र में निवेश तथा आय में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा एवं आवास पर अधिक सार्वजनिक व्यय हो।

भारत एक कृषि-प्रधान देश है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आजीविका का एक महत्वपूर्ण साधन है। स्वतंत्रता से पूर्व आय के साधन के रूप में कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण, 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका योगदान लगभग 16% है। वर्ष 1950-51 में यह हिस्सा लगभग 51% था। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से देखें तो कृषि की भागीदारी उद्योग तथा सेवा क्षेत्र की तुलना में कम है। खाद्यान्न उत्पादन जहाँ 1951-52 में मात्र 52 मिलियन टन था वहीं 2016-17 में यह बढ़कर 275.7 मिलियन टन हो गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में विकास दर लगभग 4.72% थी वहीं नौवीं, दसवीं एवं ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास दर क्रमशः 2.5%, 2.4%, 3.2% रही थी। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया है।

5.1 आर्थिक विकास में कृषि का योगदान (Contribution of Agriculture in Economic Development)

कृषि क्षेत्र का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 1950-51 में यह लगभग 51 प्रतिशत था तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में यह लगभग 14.2 प्रतिशत रह गया। राष्ट्रीय आय के आकलन की नई शृंखला (आधार वर्ष 2011-12) के आधार पर 2016-17 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र का सकल मूल्य संबद्धन (GVA) में योगदान 17.4% था। जबकि वर्ष 2017-18 में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का हिस्सा कुल जी.वी.ए. (वर्तमान कीमतों पर) में 16.4 होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। सकल मूल्य संबद्धन में कृषि के प्रतिशत योगदान में कमी अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व में गिरावट को नहीं दर्शाती है, अपितु यह केवल अर्थव्यवस्था के द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रों की सापेक्षिक तीव्र वृद्धि को दर्शाती है।

रोजगार

भारत में कृषि रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। भारत में आज भी लगभग 50% कार्यशील जनसंख्या कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।

बढ़ती हुई जनसंख्या के लिये खाद्यान्नों की आपूर्ति

भारत में कृषि क्षेत्र के उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है। वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 251.57 मिलियन टन रहा, जो कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में बढ़कर 275.7 मिलियन टन (चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) हो गया है। अतः वर्तमान में भारत को अपनी विशाल जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आयात पर निर्भर नहीं रहना पड़ रहा है।

औद्योगिक विकास के लिये कृषि क्षेत्र का महत्व

कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता के रूप में कृषि क्षेत्र अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र की संवृद्धि के लिये मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। कृषि क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक कच्चे मालों, जैसे- कपड़ा उद्योग को कपास, तेल उद्योग को तेल बीजों, चीनी उद्योग को गन्ने की आपूर्ति की जाती है। यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को कृषि उत्पादों के रूप में कच्चा माल उपलब्ध कराता है।

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण योगदान

कृषि भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। भारत चाय, जूट, काजू, तंबाकू, कॉफी और मसाले आदि का निर्यात करता है। ये सभी कृषि वस्तुएँ भारत के कुल निर्यातों का एक बड़ा प्रतिशत साझा करती हैं।

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिये औद्योगीकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। औद्योगीकरण से अर्थव्यवस्था के ढाँचे में व्यापक एवं दीर्घकालीन परिवर्तन आता है। औद्योगीकरण किसी राष्ट्र की प्रगति एवं संपन्नता का आधार ही नहीं, वरन् उसके विकास का मापदंड भी माना जाता है। तीव्र आर्थिक विकास के लिये विकासशील एवं अल्प विकसित राष्ट्रों में औद्योगीकरण को अधिक महत्ता दी जाती है।

प्राचीनकाल में भारत शिल्प, वस्त्र, रत्न-आभूषण एवं मसालों आदि के लिये प्रसिद्ध था, परंतु ब्रिटिश काल के दौरान भारतीय उद्योग पूर्णतः गर्त में चला गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश में उद्योगों के महत्त्व को दृष्टिगत रखते हुए तीव्र औद्योगीकरण हेतु योजनाबद्ध ढंग से प्रयास किये गए। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई।

नब्बे के दशक में आर्थिक मंदी का सामना करने के लिये भारत सरकार ने आर्थिक सुधारों हेतु नई आर्थिक नीति को अपनाया। नई आर्थिक नीति के द्वारा भारत में औद्योगीकरण को नई दिशा एवं दशा मिली है।

6.1 औद्योगीकरण : आशय एवं उत्पादन के क्षेत्र (Industrialization : Meaning and Sector of Production)

औद्योगीकरण का आशय राष्ट्रीय उत्पादन तथा निवेश के ढाँचे में उद्योगों की बहुलता से है, जिससे सकल घरेलू उत्पाद तथा श्रमशक्ति के प्रयोग हेतु औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ जाए। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है, जिसमें धीरे-धीरे सामान्यतया राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता जाता है तथा औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता जाता है।

दूसरे शब्दों में, प्राथमिक उत्पादों के द्वितीयक उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को औद्योगीकरण कहते हैं। यह कार्य विनिर्माण क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इसके लिये उद्योगों में निवेश अत्यंत आवश्यक है। औद्योगीकरण द्वारा राष्ट्रीय उत्पादन में, उद्योगों के उत्पादन में बहुलता एवं सकल घरेलू उत्पादन में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ाया जाता है।

उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उत्पादन क्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है-

- **प्राथमिक क्षेत्र (Primary sector) :** नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उन्हें 'प्राथमिक वस्तुएँ' कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को 'प्राथमिक क्षेत्र' कहते हैं।
- **द्वितीयक क्षेत्र (Secondary sector) :** प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्द्धन द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन्हें 'द्वितीयक वस्तुएँ' कहा जाता है तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को 'द्वितीयक क्षेत्र' कहते हैं।
- **तृतीयक क्षेत्र (Tertiary sector) :** अदृश्य सेवाओं को 'तृतीयक वस्तुएँ' कहते हैं तथा ऐसी सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को 'तृतीयक क्षेत्र' कहते हैं।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (C.S.O.) द्वारा उत्पादन क्षेत्रों का किया गया वर्गीकरण निम्नलिखित है-



राजस्थान अर्थव्यवस्था : वृहद् परिदृश्य (Rajasthan Economy : Macro Scenario)

राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किमी. है। यह देश के पश्चिमोत्तर भाग में स्थित है। इसके पूर्वोत्तर में पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश; दक्षिण-पूर्व में मध्य प्रदेश एवं दक्षिण-पश्चिम में गुजरात स्थित है। पाकिस्तान से लगी हुई राजस्थान की सुदीर्घ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। राज्य की स्थलाकृति में विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला 'अरावली' पहाड़ियों की प्रधानता है। ये पहाड़ियाँ राज्य के मध्य मार्ग से होते हुए दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर जाती हैं। इसका पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भाग मरु या अर्द्ध मरुस्थलीय है, जो वृहद् भारतीय मरुस्थल (थार का रेगिस्तान) के नाम से जाना जाता है। प्रशासनिक दृष्टि से राज्य में 7 संभाग, 33 जिले, 295 पंचायत समितियाँ, 9,891 ग्राम पंचायतें एवं 43,264 आबाद ग्राम हैं।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) एवं प्रति व्यक्ति आय (पी.सी.आई.) राज्य की अर्थव्यवस्था की समग्र उपलब्धि को प्रदर्शित करती है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद को प्रायः 'राज्य आय' के नाम से जाना जाता है, जो एक निश्चित समयावधि में राज्य के आर्थिक निष्पादन के आकलन का प्रमुख साधन है तथा यह आर्थिक विकास के स्तर में आए परिवर्तन व इसकी दिशा को इंगित करता है। प्रति व्यक्ति आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की कुल जनसंख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन स्तर एवं कल्याण की सूचक है।

राजस्थान की प्रमुख विशेषताओं का अखिल भारत से तुलनात्मक विवरण

सूचक	वर्ष	राजस्थान	भारत
भौगोलिक क्षेत्रफल (लाख वर्ग किमी. में)	2011	3.42	32.87
जनसंख्या (करोड़ में)	2011	6.85	121.09
दशकीय वृद्धि दर (%)	2001-2011	21.3	17.7
जनसंख्या घनत्व	2011	200	382
कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत	2011	24.9	31.1
अनुसूचित जाति की जनसंख्या (%)	2011	17.8	16.6
अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (%)	2011	13.5	8.6
लिंगानुपात	2011	928	943
बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष)	2011	888	919
साक्षरता दर (%)	2011	66.1	73.0
साक्षरता दर (पुरुष) (%)	2011	79.2	80.9
साक्षरता दर (महिला) (%)	2011	52.1	64.6
कार्य सहभागिता दर (%)	2011	43.6	39.8
जन्म दर (प्रति एक हजार जनसंख्या)	2016'	24.3	20.4
मृत्यु दर (प्रति एक हजार जनसंख्या)	2016	6.1	6.4
शिशु मृत्यु दर	2016	41	34
मातृ मृत्यु अनुपात (प्रति एक लाख जीवित जन्म)	2011-13	244	167
जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष)	2011-15	67.9	68.3

राजस्थान गैर-विशिष्ट श्रेणी के राज्यों में शामिल है। राजस्थान विशिष्ट श्रेणी के राज्य में शामिल किये जाने की मांग करता रहा है। धीरे-धीरे राजस्थान अब पिछड़े हुए प्रदेश से विकासशील प्रदेश में परिवर्तित हो गया है। वर्ष 1950-51 में कुल खाद्यान्न 33.8 लाख टन, 27% शुद्ध बोया क्षेत्र था, वर्ष 2017-18 में 225.82 लाख टन खाद्यान्न उत्पादन होने की संभावना तथा शुद्ध बोया क्षेत्र 52.60% है।

राजस्थान की अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन के कारण (Reason of backwardness of Rajasthan's economy)

- भौगोलिक स्थिति:** अरावली के पश्चिम में थार का मरुस्थल पाया जाता है। इस क्षेत्र में वनस्पतियों का अभाव, वर्षा की कमी, परिवहन सुविधा का अभाव आदि के कारण यह क्षेत्र पूर्ण विकसित नहीं हो पाया है।
- प्राकृतिक बाधाएँ:** वर्षा की अनिश्चितता, अकाल, सूखा, पानी की समस्या, भूमि का कटाव आदि कारकों के कारण कृषि, पशुपालन, उद्योगों आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कृषि की मानसून पर निर्भरता अधिक है।
- विद्युत शक्ति का अभाव:** वर्ष 1950-51 में 13 मेगावाट क्षमता थी, जो वर्तमान में बढ़कर लगभग 17,439 मेगावाट हो गई है। इसके बावजूद अभी भी राजस्थान विद्युत क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया।
- अवसंरचना की कमी:** सड़क परिवहन, रेल परिवहन तथा बंदरगाह से दूरी आदि बाधक तत्व हैं। अभी भी बहुत से कस्बों तक परिवहन की व्यवस्था सुचारु नहीं हुई है। रेल परिवहन का विद्युतीकरण, डबल ट्रैक की कमी, तहसीलों तक रेल परिवहन का अभाव आदि कमियाँ अभी भी विद्यमान हैं।
- सिंचाई के साधनों का अभाव:** वर्ष 2014-15 तक कुल बोए गए क्षेत्र का लगभग 42% ही सिंचाई के अंतर्गत आता है। इसी कारण एक से अधिक फसल बोना संभव नहीं।
- खनिज व ईंधन का अभाव:** राजस्थान में कच्चा लोहा व कोयले का अभाव है। ईंधन के अभाव से वृहद् उद्योगों का विकास नहीं हो पाया है।
- जनसंख्या वृद्धि, बेरोज़गारी:** राजस्थान की दशकीय वृद्धि 21.3% है, जो राष्ट्रीय वृद्धि से अधिक है। जनसंख्या वृद्धि का भार बढ़ने से बेरोज़गारी की समस्या बढ़ रही है। इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप और वित्तीय साधनों की कमी से समस्या जटिल हो गई है।
- वित्तीय साधनों का अभाव:** आर्थिक विकास की प्रगति के लिये पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधनों की आवश्यकता होती है। वर्ष 2017 तक चालू कीमतों पर कुल योजना व्यय 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। राज्य पर बकाया कर्ज़ का भार बढ़ता जा रहा है। विद्युत क्षेत्र में उचित निवेश के बावजूद उचित प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है।
- अन्य कारण:** सामाजिक पिछड़ापन, कुशल श्रमिकों का अभाव, शिक्षा स्तर, प्रशासन में पारदर्शिता का अभाव आदि अन्य कारक हैं।

पंचवर्षीय योजनाएँ (Five year plans)

पंचवर्षीय योजनाएँ (Five Year Plans)			
योजना	स्वीकृत व्यय (करोड़)	वास्तविक व्यय (करोड़)	अन्य विवरण
प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56)	64.50	54.15	कृषिगत उत्पादन बढ़ाना, शिक्षा, सिंचाई की सुविधाओं को बढ़ाना।
द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-61)	105.27	102.74	सिंचाई, ऊर्जा, सामाजिक सेवाओं पर बल तथा पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण।

राजस्थान में विकास के विविध आयाम (Various Dimensions of Development in Rajasthan)

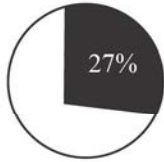
विकास एक बहुआयामी अवधारणा है। इसका संबंध आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, क्षेत्रीय, मानवीय समेत सभी क्षेत्रों से होता है। विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दे एवं विषय भी विविध एवं बहुआयामी होते हैं। इसमें आर्थिक विकास के संबंध में कृषिगत, उद्योग तथा सेवा क्षेत्र के मुद्दे प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। वहीं सामाजिक विकास के संबंध में निर्धनता, बेरोजगारी जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। क्षेत्रीय विकास सभी क्षेत्रों तथा स्तरों पर समान विकास की अपेक्षा से संबंधित होता है। मानव विकास व्यापक रूप में मानव जीवन के सभी बुनियादी विषयों से जुड़ाव रखता है।

9.1 सामाजिक विकास के आयाम (Dimensions of Social Development)

समाज के सभी वर्गों का समग्र विकास करना राज्य सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी एवं स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ सामाजिक विकास के लिये सर्वप्रमुख बाधाएँ हैं। सरकारों द्वारा सामाजिक विकास को गति देने के लिये निरंतर कदम उठाए गए हैं।

राजस्थान में निर्धनता (Poverty in Rajasthan)

विश्व बैंक के अनुसार भारत में 27 करोड़ लोग गरीब हैं, उनमें से 62% गरीब व्यक्ति सात राज्यों में हैं। जिनमें राजस्थान भी शामिल है। गरीब व्यक्तियों में से 80% ग्रामीण इलाकों व कस्बों में रहते हैं।



27% गरीब (छोटे गाँव)
(जनसंख्या- 0-4999)



19% गरीब (बड़े गाँव)
(जनसंख्या- 5000+)



17% गरीब (छोटे कस्बे)
(10 लाख तक जनसंख्या)



6% गरीब (बड़े शहर)
(10 लाख से अधिक जनसंख्या)

	तेंदुलकर विधि			रंगराजन		
	(2011-12) (प्रतिशत)			(2011-12) (प्रतिशत)		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
राजस्थान	14.7	16.1	10.7	21.7	21.4	22.5
भारत	21.9	25.7	13.7	29.5	30.9	26.4

राजस्थान में गरीबी के कारण

आर्थिक कारण

- कृषि पर निर्भरता
- भौगोलिक परिस्थितियाँ
- निम्न प्रति व्यक्ति आय
- बड़े उद्योगों की कमी
- बेरोजगारी
- प्राकृतिक आपदाएँ
- कुशल श्रमिक का अभाव

सामाजिक कारण

- अशिक्षा
- जनसंख्या वृद्धि
- महिलाओं की सहभागिता में कमी
- रूढ़िवाद
- जनजातीय समाज
- सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता

राजनीतिक कारण

- नीतियों के बेहतर क्रियान्वयन में कमी
- भूमि-सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव

बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करती है। लोग अपनी बचत राशि को सुरक्षा की दृष्टि से अथवा ब्याज कमाने हेतु इन संस्थाओं में जमा करते हैं और आवश्यकतानुसार समय-समय पर निकालते रहते हैं। बैंक इस प्रकार जमा से प्राप्त राशि को व्यापारियों एवं व्यवसायियों को ऋण देकर ब्याज कमाते हैं। आर्थिक नियोजन के वर्तमान युग में कृषि, उद्योग एवं व्यापार के विकास के लिये बैंक एवं बैंकिंग व्यवस्था एक अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है। दूसरी ओर, वित्तीय प्रणाली से आशय बाजार की संस्थाओं से है जो कि अर्थव्यवस्था में बचत को बढ़ाने तथा उसके कुशलतम प्रयोग की गतिशीलता बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

10.1 मुद्रा और बैंकिंग (Money and Banking)

मुद्रा (Money)

मिल्टन फ्रीडमैन के अनुसार, “मुद्रा ऐसी कोई भी संपत्ति है जिसमें क्रयशक्ति के अस्थायी निवास के रूप में कार्य करने की क्षमता हो।” दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि “मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है।” मुद्रा की उत्पत्ति विनिमय के माध्यम के रूप में हुई है। अतः कोई भी वस्तु जो सभी प्रकार के व्यवहारों (जिसमें ऋण भी सम्मिलित है) को पूरा करने में भुगतान के माध्यम के रूप में सामान्यतया स्वीकार की जाती है, उसे ‘मुद्रा’ कहते हैं।

मुद्रा के प्रकार (Type of money)

मुद्रा के दो प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं:

- **वैधानिक मुद्रा (Legal currency)** : वह मुद्रा जिसका निर्गमन सरकार या भारतीय रिज़र्व बैंक ने किया है। वैधानिक मुद्रा में रिज़र्व बैंक धारक को उतनी रकम अदा करने का वचन देता है, जितने मूल्य की करेंसी है।
- **साख मुद्रा (Credit money)** : वह मुद्रा जिसका भुगतान चेक या अन्य माध्यमों से किया जाता है। यह एक ऐच्छिक मुद्रा है, जिसे स्वीकार करना व्यक्ति की बाध्यता नहीं है। सामान्यतः साख मुद्रा के 5 रूप प्रचलित हैं— प्रतिज्ञा-पत्र (Bond), चेक (Cheque), हुंडी (Hundi), विनिमय-पत्र (Exchange Deed), बैंक-ड्राफ्ट (Bank Draft)

सांकेतिक मुद्रा (Token money)

यह वह मुद्रा होती है जिसका आंतरिक धात्विक मूल्य उसके अंकित मूल्य से कम होता है। यह सस्ती धातु से बनी होती है। उदाहरण- भारतीय सिक्के।

प्रामाणिक मुद्रा (Standard money)

यदि सिक्के का वास्तविक एवं अंकित मूल्य बराबर हो तो उसे ‘प्रामाणिक मुद्रा’ कहते हैं। सोने और चांदी के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा ही होते हैं।

प्लास्टिक मनी (Plastic money)

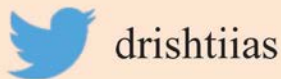
विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य कंपनियों द्वारा जारी किये गए डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड आदि को ‘प्लास्टिक मनी’ कहा जाता है। डेबिट कार्ड के द्वारा बैंक खाते में जितनी धनराशि जमा हो उतने तक ही खरीदारी या निकासी की सुविधा होती है, जबकि क्रेडिट कार्ड से बैंक खाते में धनराशि न होने पर भी कुछ निकासी या खरीदारी की जा सकती है।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीजन हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com

E-mail : online@groupdrishti.com



641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456